English → Hindi

Austlii
तस्मानिया विश्वविद्यालय लॉ रिव्यू

कुने, रान्डेल --- "अदालत में चोरी की पीढ़ियाँ: चोरी की पीढ़ियों के सदस्यों द्वारा व्यापक सफल मुकदमेबाजी की कमी की व्याख्या" [2011] UTasLawRw 2; (2011) 30(1) यूनिवर्सिटी ऑफ़ तस्मानिया लॉ रिव्यू 32

I. प्रस्तावना
II विंडशटल के तर्क
III मुकदमेबाजी में बाधाएं और हतोत्साहन
क. कानूनी बाधाएं
बी साक्ष्य संबंधी बाधाएं
सी प्रक्रियागत बाधाएं
डी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं
ई क्षतिपूर्ति की अपर्याप्तता
चतुर्थ निष्कर्ष

अदालत में चोरी की पीढ़ियाँ: चोरी की पीढ़ियों के सदस्यों द्वारा व्यापक सफल मुकदमेबाजी की कमी की व्याख्या

रैंडल कुन [*]

'मैं चाहता हूँ कि यदि कोई बड़ा खर्च न करना पड़े तो बच्चे को वापस मिल जाना चाहिए; अन्यथा विभाग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच सकती है।' [1]

'बच्चों का कब्ज़ा भविष्य के स्वामित्व का संकेत देता है।' [2]

I. प्रस्तावना

यह लेख चोरी की पीढ़ियों के सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से सफल मुकदमेबाजी की कमी के कारणों की जांच करता है। 'चोरी की पीढ़ी' शब्द का तात्पर्य ऑस्ट्रेलियाई सरकारों द्वारा नस्लीय कारणों से 1800 के दशक के अंत से 1970 के दशक तक अपने परिवारों और संस्कृति से जबरन हटाए गए स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई बच्चों से है। [3] हालाँकि हटाए गए आदिवासी बच्चों की संख्या के बारे में बहस जारी है, [4] इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकारियों ने इस दौरान कई हज़ार आदिवासी बच्चों को उनके माता-पिता से जबरन हटा दिया। [5]

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार और समान अवसर आयोग (HEROC) ने 1997 में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीप वासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर उन्हें घर वापस लाने के संबंध में राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट में इन निष्कासनों को अनैतिक और कुछ परिस्थितियों में अवैध घोषित किया था:

> स्वदेशी बच्चों को हटाने की ऑस्ट्रेलियाई प्रथा में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित व्यवस्थित नस्लीय भेदभाव और नरसंहार दोनों शामिल थे। फिर भी यह संधियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित होने के बाद भी आधिकारिक नीति के रूप में लंबे समय तक जारी रहा, जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे। [6]

आयोग ने आगे कहा कि, यद्यपि बच्चों को हटाना कानूनी रूप से अधिकृत हो सकता है, फिर भी यह भेदभावपूर्ण और नरसंहारकारी है:

> जांच में पाया गया है कि मजबूरी, दबाव या अनुचित प्रभाव से स्वदेशी बच्चों को हटाना आमतौर पर कानून द्वारा अधिकृत था, लेकिन उन कानूनों ने मौलिक सामान्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया, जिसका स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अन्य सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ समान रूप से आनंद लेना चाहिए था। [7]

कीथ विंडशटल ने द फैब्रिकेशन ऑफ एबोरिजिनल हिस्ट्री वॉल्यूम 3: द स्टोलन जेनरेशन्स 1881-2008 में एक विपरीत स्थिति ली है :

> मेरा निष्कर्ष यह है कि न केवल नरसंहार का आरोप अनुचित है, बल्कि 'चोरी हुई पीढ़ी' शब्द भी अनुचित है। आदिवासी बच्चों को आदिवासीपन को खत्म करने या वास्तव में किसी अनुचित सरकारी नीति या कार्यक्रम की सेवा करने के लिए उनके परिवारों से कभी नहीं हटाया गया। बीसवीं सदी में आदिवासी बच्चों को हटाने की छोटी संख्या लगभग सभी बाल कल्याण के पारंपरिक आधार पर आधारित थी। [8]

उनका दावा है कि स्टोलन जेनरेशन के सदस्यों द्वारा व्यापक रूप से सफल मुकदमेबाजी की कमी इस निष्कर्ष का समर्थन करती है। सरल शब्दों में कहें तो, उनका कहना है कि 'अगर स्टोलन जेनरेशन की कहानी सच होती, तो इसके सदस्यों को अब तक अदालतों में कई जीत मिल चुकी होतीं।' [9]

हालाँकि विंडशटल का तर्क अवास्तविक और अतार्किक है, लेकिन चोरी की पीढ़ियों के मुकदमों में आने वाली कई बाधाओं और हतोत्साहनों की प्रकृति और सीमा सबसे अच्छी तरह से अटकलें हैं, और आगे के विश्लेषण और अनुभवजन्य शोध की आवश्यकता है। इस विश्लेषण और शोध की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि गैर-स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की कम जीवन प्रत्याशा को देखते हुए, संबंधित लोगों में से कई अपने जीवन के अंत के करीब हैं।

चोरी की पीढ़ियों के अस्तित्व और सीमा के बारे में बहस, गलत तरीके से हटाए जाने के शिकार बच्चों और आम तौर पर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों दोनों के लिए न्याय तक पहुँच की संभावित कमी के बारे में व्यापक चिंताएँ पैदा करती है। यह बहस उन आदिवासी और गैर-आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को न्याय प्रदान करने में कानूनी प्रणाली की अक्षमता को भी उजागर करती है जो प्रणालीगत गलत कामों के शिकार रहे हैं।

II विंडशटल के तर्क

विंडशटल ने नोट किया कि चोरी की पीढ़ियों के समर्थकों का आरोप है कि 50,000 से 100,000 बच्चों को हटा दिया गया था। [10] यह सीमा, विंडशटल का कहना है, संभावित चोरी की पीढ़ियों के वादियों का समूह है। बाद में वह इस आंकड़े के विपरीत निष्कर्ष निकालता है कि अनुमान 8,250 है। [11] जो भी संख्या हो, विंडशटल यह पहचानने में विफल रहता है कि चोरी की पीढ़ियों के सभी सदस्य संभावित मुकदमेबाज नहीं हैं। कुछ की मृत्यु हो गई है। कुछ उम्र, बीमारी या विकलांगता से अक्षम हो जाएंगे। अन्य चोरी की पीढ़ियों की अपनी सदस्यता से अनभिज्ञ होंगे। [12] वे नहीं जानते होंगे कि उन्हें ले जाया गया था, या क्यों, और उन्हें संदेह नहीं हो सकता है कि उनके पास आदिवासी विरासत है। ऐसे लोगों को संभावित वादियों के समूह से बाहर रखा जाना चाहिए।

विंडशटल ने स्वीकार किया कि स्टोलन जेनरेशन के वादियों को कुछ संभावित हतोत्साहन और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन पर कम ध्यान दिया जाता है। इसके बजाय, वह एक काल्पनिक मूल्य निर्णय लेता है कि मुकदमा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन किसी भी हतोत्साहन से अधिक होगा। वह स्टोलन जेनरेशन के एकमात्र सफल वादी, ब्रूस ट्रेवोर को 2007 में $525,000 प्लस $250,000 ब्याज की राशि के मुआवजे के पुरस्कार का उल्लेख करता है, [13] और लिखता है कि 'हालांकि यह सच है कि कानूनी कार्रवाई एक कठिन प्रक्रिया है और परिणाम देने में सालों लग सकते हैं, ऐसे संभावित मुआवजे के साथ वास्तविक मामलों के लिए प्रयास स्पष्ट रूप से इसके लायक होंगे।' [14] यह विशेष रूप से ऐसा है, वह जारी रखता है, संभावित वादियों के विशाल पूल को देखते हुए, [15] विंडशटल कानूनी व्यवस्था के भीतर जड़ जमाए हुए नस्लवादी और जातीय-केंद्रित सोच के अस्तित्व के बारे में चिंता को स्वीकार करते हैं, लेकिन निष्कर्ष निकालते हैं कि *माबो* [17] और *विक* में उच्च न्यायालय के स्वदेशी समर्थक फैसलों के मद्देनजर इस तर्क पर 'विश्वास करना कठिन' है [16] । [18]

कुल मिलाकर, विंडशटल का तर्क अतार्किक और अवास्तविक है। उनका दावा है कि नैतिक और सामाजिक गलत (नस्लीय कारणों से आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से जबरन हटाना) नहीं हुआ क्योंकि सफल मुकदमेबाजी के माध्यम से व्यापक मान्यता नहीं मिली है कि ये गलतियां मुआवज़े योग्य *कानूनी* गलतियां भी थीं। उनका तर्क अतार्किक है क्योंकि यह कानूनी गलत काम के सबूत की कमी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि यह साबित हो सके कि कोई सामाजिक या नैतिक गलत काम नहीं हुआ। *ब्रिंग देम होम* [19] और पूर्व प्रधानमंत्री केविन रुड ने चोरी की पीढ़ियों के लिए अपने माफ़ीनामे में सामाजिक या नैतिक गलत को मान्यता दी। [20] नैतिक गलत काम हटाने के कानूनों, नीतियों और प्रथाओं की नस्लवादीता में निहित है, जिस तरह से आदिवासी बच्चों को गैर-आदिवासी बच्चों से अलग तरीके से निपटाया जाता है, [21] यह धारणा कि गोरे बच्चों के पालन-पोषण की प्रथाएँ आदिवासी लोगों की तुलना में बेहतर थीं, [22] और गैर-स्वदेशी देखभालकर्ताओं के साथ रखे गए चुराए गए बच्चों की पहचान और संस्कृति को नष्ट करने में। [23]

विंडशटल का तर्क भी अवास्तविक है। मुकदमेबाजी इतिहास का खराब न्याय है। सफल मुकदमेबाजी की कमी को व्यापक ऐतिहासिक सत्य के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अधिक विशेष रूप से, अदालत के फैसले इतिहास को बनाने वाले 'सामान्य पैटर्न, कारण और परिणाम' को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। [24] इसके कारणों का परीक्षण की प्रतिकूल प्रणाली की प्रकृति से बहुत कुछ लेना-देना है।

कार्यवाही लाने वाले वादियों पर अपने आरोप को सबूत के अपेक्षित मानक पर साबित करने का दायित्व होता है, जो ऑस्ट्रेलिया भर में नागरिक अधिकार क्षेत्रों में संभावनाओं के संतुलन पर होता है। यह 'किसी भी तरह से सत्य की खोज' नहीं है। [25] मुकदमे प्रक्रिया और साक्ष्य के नियमों के अनुसार चलाए जाते हैं, जो कि दलील दी गई कार्रवाई के कारणों द्वारा तैयार प्रासंगिकता के परीक्षण के संदर्भ में होते हैं। यदि आवेदक का मामला विफल हो जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जिस आचरण की शिकायत की गई है, वह कानून का उल्लंघन नहीं था। हालांकि, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वे सबूत के मानक को पूरा करने में विफल रहे।

मामलों का निर्णय पक्षों द्वारा प्रस्तुत (या सहमत) साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। यह पक्षों पर निर्भर करता है कि वे अपने मामले का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करें। यदि कोई पक्ष अपने मामले को संतुलित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, या विवाद में प्रासंगिक मुद्दों पर प्रभावी ढंग से बहस नहीं करता है, तो वे हार जाएँगे। इसका मतलब यह नहीं है कि कथित घटनाएँ नहीं हुईं, हालाँकि यह अदालत के फैसले का कानूनी प्रभाव है। [26] साबित किए जाने वाले तथ्य वे होने चाहिए जो दलील दी गई कार्रवाई के कारण से संबंधित हों, न कि ऑस्ट्रेलियाई स्वदेशी नीति और अभ्यास की पृष्ठभूमि के लिए अधिक व्यापक रूप से प्रासंगिक साक्ष्य। [27]

III मुकदमेबाजी में बाधाएं और हतोत्साहन

चोरी की पीढ़ियों के कुछ मुखर समर्थकों और विरोधियों द्वारा दिए गए तर्क ध्रुवीकृत, अक्सर असंतुलित, [28] रहे हैं और साक्ष्य कभी-कभी नैतिकतावादी और भावनात्मक भाषा और व्यापक सामान्यीकरण द्वारा अस्पष्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित अनुभाग में, लेखक चोरी की पीढ़ियों के अस्तित्व को साबित या अस्वीकृत करने, 'चोरी' या 'पीढ़ियों' शब्दों के बारे में भाषाई बहस में शामिल होने, [29] या 'इतिहास युद्धों' में प्रवेश करने [30] का इरादा नहीं रखता है, लेकिन बहस का एक संतुलित दृष्टिकोण लेने का प्रयास करता है।

क. कानूनी बाधाएं

क्रूगर बनाम कॉमनवेल्थ में , [31] नौ आदिवासी वादियों ने कानून की संवैधानिक अमान्यता पर जोर दिया, जिसने कथित तौर पर उनमें से आठ को बच्चों के रूप में हटाने, और उनमें से एक के बच्चे को हटाने को अधिकृत किया। [32] उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कार्रवाई का एक कारण मौजूद है जो उन्हें व्यक्त और निहित संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हर्जाने का हकदार बनाता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उत्तरी क्षेत्र के *आदिवासी अध्यादेश 1918* की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया , [33] क्योंकि यह *संविधान* की धारा 122 के तहत राष्ट्रमंडल कानून बनाने की शक्ति के भीतर था ; [34] इसने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया; [35] इसने *संविधान* की धारा 116 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया ; [36] और, इसने आंदोलन और संघ की स्वतंत्रता [37] या समानता [38] के किसी भी निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जो मौजूद हो सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन टोर्ट या अनुबंध के बाहर नुकसान के लिए कार्रवाई के किसी नए कारण को जन्म नहीं देता है। [39]

उच्च न्यायालय ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि *अध्यादेश* नरसंहार के उद्देश्य से लागू किया गया था या इसका उद्देश्य एक नस्लीय समूह को नष्ट करना था, लेकिन इसके विपरीत माना कि यह इरादे में फायदेमंद था। [40] हालांकि, बहुमत ने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या *संविधान* अन्यथा नरसंहार कानून को सीमित करेगा, [41] इस संभावना को भविष्य के मुकदमे के लिए खुला छोड़ दिया। निर्णय ने उस या समान शक्ति के *दुरुपयोग के लिए हर्जाने की संभावना को भी खुला छोड़ दिया।* [42] मुख्य न्यायाधीश ने जोर दिया कि दुरुपयोग का आकलन उस समय के मानकों से किया जाना चाहिए न कि समकालीन मानकों से। [43] यह साबित करना मुश्किल हो गया कि समय के मानकों से अनुचित होने के आधार पर हटाना अधिकार के बिना था। [44] *क्यूबिलो बनाम कॉमनवेल्थ* में इस पर बहस की गई । [45] यह सफल नहीं हुआ। [46]

क्यूबिलो में संघीय न्यायालय ने *क्रूगर* के समान ही कानून पर विचार किया , लेकिन आवेदकों, लोर्ना क्यूबिलो और पीटर गननर ने दावा किया कि, उनके निष्कासन से, राष्ट्रमंडल (अपने एजेंट, मूल निवासी मामलों के निदेशक के माध्यम से) ने लापरवाही, गलत

कारावास और वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के साथ-साथ आवेदकों के प्रति अपने प्रत्ययी कर्तव्यों का उल्लंघन किया। सीमाओं का क़ानून आवेदकों की सफलता की कमी का प्राथमिक कारण था। *क्यूबिलो* में न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं था कि प्रतिवादी को देरी से होने वाले पूर्वाग्रह के कारण सीमाओं की अवधि का विस्तार करना न्यायसंगत और उचित था। [[47] हालांकि, न्यायालय ने इस आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी कि विस्तार आवेदन के बारे में एक औपचारिक खोज इसके निष्कर्ष पर की जाएगी। [48] ऐसा करने में, उनके सम्मान ने निर्धारित किया कि अंधाधुंध निष्कासन की कोई नीति या प्रथा नहीं थी [49] और न ही कानून में या मूल निवासी मामलों के निदेशक और अन्य द्वारा इसके प्रशासन में कोई नरसंहार का इरादा था [50] :

> साक्ष्यों से पता चला कि 1940 और 1950 के दशक में ऐसे लोग थे जो आदिवासी लोगों की देखभाल करते थे। उन लोगों को लगता था कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में काम कर रहे थे। बाद की घटनाओं से पता चला है कि वे गलत थे। हालाँकि, यह संभव है कि वे वैधानिक शक्तियों के अनुसार काम कर रहे थे या, शायद इन दो दावों में, यह कहना अधिक सटीक होगा कि आवेदकों ने यह साबित नहीं किया है कि उन्होंने अपनी शक्तियों से परे काम किया। [51]

लोर्ना क्यूबिलो के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि उनके पास मूल निवासी मामलों के निदेशक के खिलाफ गलत कारावास का प्रथम दृष्टया मामला था, लेकिन राष्ट्रमंडल प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी नहीं था। [52] भले ही समय के बाहर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई हो, उसकी कार्रवाई विफल हो जाएगी क्योंकि उसने उचित प्रतिवादी पर मुकदमा नहीं किया था। पीटर गनर की मां टॉप्सी को उनके निष्कासन के लिए सहमति देते हुए पाया गया था, और इसलिए अतिचार या गलत कारावास में कोई दावा सफल नहीं हो सकता था। [53] न तो लोर्ना क्यूबिलो और न ही पीटर गनर वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन स्थापित कर सके। [54] राष्ट्रमंडल पर किसी भी आवेदक के प्रति लापरवाही में देखभाल का कोई सामान्य कानूनी कर्तव्य नहीं था। [55] न्यायालय ने पाया कि निदेशक को निष्कासन के समय देखभाल का कर्तव्य नहीं था [57] लोर्ना क्यूबिलो के मामले में, कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया गया था, लेकिन पीटर गनर के मामले में ऐसा हुआ था। [58] हालाँकि, कर्तव्य निदेशक द्वारा वहन किया जाना था, जिस पर मुकदमा नहीं चलाया गया था, और राष्ट्रमंडल प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी नहीं था। [59] इस प्रकार, दोनों लापरवाही की कार्रवाइयाँ विफल हो गईं।

न्यू साउथ वेल्स में, जॉय विलियम्स को समय से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी, [60] लेकिन 1999 में अपने मूल दावों में असफल रहीं। [61] *आदिवासी संरक्षण अधिनियम 1909* (NSW) के तहत उनकी मां से आदिवासी कल्याण बोर्ड को संरक्षकता हस्तांतरित नहीं की गई थी , हालांकि वह अधिनियम के तहत 'वार्ड' बन गई थीं। अतिचार में उनका दावा विफल हो गया, क्योंकि यह स्वीकार किया गया कि उनकी मां ने उनकी देखभाल में नियुक्ति के लिए सहमति दी थी, [62] और यह बोर्ड की वैधानिक शक्तियों के अनुसार किया गया था। [63] उनके लिए कोई कार्रवाई योग्य वैधानिक कर्तव्य नहीं था [64] क्योंकि '[अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य बाल कल्याण कानून की प्रकृति, दायरे और शर्तों के संदर्भ में अपकृत्य में कार्रवाई का अधिकार प्रदान करना नहीं था'। [65] माननीय न्यायाधीश ने माना कि कोई प्रत्ययी कर्तव्य उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, तो भी परिस्थितियों में इसका उल्लंघन नहीं हुआ, न ही कथित उल्लंघन के कारण कथित नुकसान हुआ होगा। [66] देखभाल का कोई कर्तव्य मौजूद नहीं था, [67] और इसलिए लापरवाही में वादी का दावा विफल हो गया। वैकल्पिक रूप से, न्यायालय ने पाया कि अगर ऐसा कोई कर्तव्य था तो उसका उल्लंघन नहीं हुआ था, [68] और किसी भी दर पर नुकसान किसी कथित उल्लंघन के कारण नहीं हुआ था। [69] न्यायालय द्वारा देखभाल के कर्तव्य की एक नई श्रेणी बनाने से इनकार करने के कारणों में से एक यह जोखिम था कि ऐसा करने से, सरकारी देखभाल में मनोवैज्ञानिक रूप से घायल लोगों द्वारा मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी। [70] एक अन्य नीतिगत कारण यह था कि राज्य को अपने देखभाल में बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में माता-पिता से अलग स्थिति में नहीं होना चाहिए। [71]

प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुआवजे का दावा किया गया था, [72] और *विलियम्स* , [73] *क्यूबिलो* , [74] और *दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य बनाम लैंपार्ड-ट्रेवोर* , [75] में मुख्य रूप से इस आधार पर विफल रहा कि बच्चों को राज्य की देखभाल में ले जाने से उस प्रकार का प्रत्ययी कर्तव्य नहीं बनता है जहां गैर-आर्थिक चरित्र के उल्लंघन से नुकसान हो सकता है। [76]

लापरवाही के दावों को बंद नहीं किया जाता है, जैसा कि रॉल्फ जे ने जॉनसन में समय विस्तार के आवेदन में निष्कर्ष निकाला था , [77] विशेष रूप से देखभाल के एक नए कर्तव्य को कब बनाया जाएगा, इस संबंध में लापरवाही के कानून की भ्रमित स्थिति को देखते हुए। [78 *] इस पर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य बनाम लैंपार्ड-ट्रेवरो* द्वारा जोर दिया गया है , [79] जिसमें दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई पूर्ण न्यायालय ने सार्वजनिक कार्यालय में लापरवाही और दुराचार के लिए मुआवजे के पुरस्कार की अनुमति दी थी। वह मामला *ट्रेवरो बनाम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया (सं. 5)* में ग्रे जे के फैसले के खिलाफ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य द्वारा अपील था । [80] क्रिसमस 1957 के आसपास, वादी, ब्रूस ट्रेवरो, उम्र 1, को गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जल्दी ठीक हो गया। उन्हें 6 जनवरी 1958 को

आदिवासी विभाग द्वारा अस्पताल से हटा दिया गया और श्री और श्रीमती डेविस को सौंप दिया गया, *आदिवासी अधिनियम ने* कुछ निष्कासन शक्तियाँ दी थीं, लेकिन 1949 में, क्राउन सॉलिसिटर ने अटॉर्नी-जनरल को औपचारिक सलाह दी थी कि *आदिवासी अधिनियम 1934-1939* की धारा 7 आदिवासी बच्चों को उनके माता-पिता से जबरन हटाने का अधिकार नहीं देती है। [81] यह सलाह कैबिनेट और आदिवासी संरक्षण बोर्ड (APB) के सदस्यों को वितरित की गई थी। 1954 में सलाह की पुष्टि की गई। [82]

जैसा कि वादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, वह गंभीर अवसाद और शराब के दुरुपयोग से पीड़ित था, जिसके कारण उसकी कमाई करने की क्षमता खत्म हो गई और मानसिक बीमारी जारी रही। वह आश्रय वाले काम में लगा हुआ था, उसकी शादी में घरेलू हिंसा की वजह से रुकावटें आईं, वह कभी अपने बच्चों के करीब महसूस नहीं करता था और वह कभी भी अपनी स्वदेशी संस्कृति से जुड़ा नहीं था। [83]

दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्यायालय ने ट्रायल जज के कुछ निष्कर्षों की पुष्टि की, लेकिन अन्य को उलट दिया। [84] पूर्ण न्यायालय ने पुष्टि की कि एपीबी या वैकल्पिक रूप से आदिवासी विभाग के सचिव ब्रूस को सहमति के बिना हटाने के लिए सार्वजनिक कार्यालय में दुर्व्यवहार के अपराध के लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी शक्ति से परे था और नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता था। [85] क्राउन परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। [86] एपीबी का वादी के प्रति यह कर्तव्य भी था कि वह उसे उसकी मां की देखभाल और संपर्क से हटाकर चोट पहुंचाने से बचाए। [87] *क्यूबिलो* के फैसले के विपरीत , पूर्ण न्यायालय ने माना कि कर्तव्य का पालन किया जाना था चाहे एपीबी के पास कार्रवाई करने का वैधानिक अधिकार था या नहीं। [88] न्यायालय ने वास्तविक माता-पिता के कर्तव्य को एपीबी जैसे निकायों के कर्तव्यों से अलग किया, [89] और इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस तरह का कर्तव्य बाल संरक्षण निर्णय लेने पर संभावित रूप से नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा। [90]

दूसरी ओर, पूर्ण न्यायालय ने दो प्रमुख मामलों में ट्रायल जज के निष्कर्षों को पलट दिया। सबसे पहले, एक बच्चे की देखभाल करने वाले परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए कोई गलत कारावास नहीं था। [91] दूसरा, हालांकि एक प्रत्ययी कर्तव्य संभव था, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। [92] ट्रायल जज के कारण और क्षतिपूर्ति पुरस्कार का आकलन बिना किसी चुनौती के चला गया, [93] लेकिन मामले का मिसाल मूल्य एपीबी द्वारा देखभाल के कर्तव्य के विस्तार और सार्वजनिक कार्यालय में दुर्व्यवहार के सिद्धांतों के प्रतिपादन में निहित है। समान मामलों में, अन्य चोरी पीढ़ी के मुकदमेबाजों को भी इसी तरह की सफलता का सामना करना पड़ सकता है। बहुत कुछ हटाने के समय हटाने के प्रभावों के ज्ञान की स्थिति पर निर्भर करता है। [94]

कुछ लेखक न्यायिक प्रक्रिया में अचेतन नस्लवाद की पहचान करते हैं। [95] रॉबर्ट मैन का दावा है कि ओ'लॉघलिन जे ने अपने अचेतन नस्लवाद के कारण निष्कासन की नीति पर ऐतिहासिक डेटा की सही व्याख्या नहीं की:

> न्यायमूर्ति ओ'लफलिन सही हैं जब उन्होंने तर्क दिया कि जिन लोगों ने बच्चों को उनकी माताओं, परिवारों और समुदायों से अलग किया, उन्होंने सोचा कि वे 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में' काम कर रहे हैं। वह यह नहीं देख पाते हैं कि 'अर्ध-जाति' के बच्चे के सर्वोत्तम हित के बारे में उनकी धारणा कितनी गहराई से निर्विवाद रूप से नस्लवादी धारणाओं द्वारा निर्धारित की गई थी। [96]

असफल अपकृत्य और न्यायसंगत दावे न्यायपालिका के लिए एक चुनौती हैं कि वह 'अपकृत्य और इक्विटी के सिद्धांतों को इस तरह से विकसित करे जो ऑस्ट्रेलिया के आत्मसात इतिहास के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट नुकसानों के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार कर सके।' [97] उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियाई न्यायशास्त्र अंग्रेजी कानून अवधारणाओं से प्राप्त कानूनी मान्यताओं और अवधारणाओं से खुद को मुक्त कर सकता है, जो ऑस्ट्रेलियाई औपनिवेशिक बसने वाले संदर्भ के लिए अद्वितीय ऐतिहासिक वास्तविकता से रहित हैं। [98]

अन्य लोगों ने कानूनी व्यवस्था की 'मुक्तिदायक' भूमिका पर सवाल उठाए हैं। [99] जबकि नस्लीय भेदभाव का आरोप उचित हो सकता है, [100] नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से व्यवहार को उस समय के मानकों के आधार पर आंका जाना चाहिए। इसी तरह के कारणों से, नरसंहार के आरोप को इस आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि निष्कासन के समय यह एक सामान्य कानून अपराध नहीं था। [101] *यहां तक कि ट्रेवोर* में भी , जहां सार्वजनिक कार्यालय में दुर्व्यवहार सिद्ध पाया गया था, न्यायालय ने कानून निर्माताओं और प्रशासकों के लाभकारी इरादे को स्वीकार किया, हालांकि वर्तमान मानकों के अनुसार न्याय किए जाने पर यह गुमराह करने वाला था।

बी साक्ष्य संबंधी बाधाएं

उन्हें घर लाने की जांच की एकतरफा होने के रूप में आलोचना की गई है, क्योंकि हटाए जाने और देखभाल में उपचार के बारे में दी गई गवाही का जिरह में गहन विश्लेषण और परीक्षण नहीं किया गया था। [102] न ही यह गलत काम करने के आरोपी लोगों द्वारा खंडन या तर्क का विषय था। वास्तव में, कथित रूप से नरसंहार और भेदभावपूर्ण कानूनों और नीतियों को स्थापित या लागू करने वालों से कोई गवाही नहीं मांगी गई थी, [103] भले ही आयोग के पास गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने की शक्ति थी। [104] आपराधिक आरोपों वाले उन नीति निर्माताओं, विधायकों या प्रशासकों में से किसी की भी आगे की जांच या अभियोग लगाने के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं की गईं। जांच का उपयोग उन लोगों के लिए एक अवसर के रूप में किया गया था जिन्हें हटा दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, ताकि वे अपने अनुभव को आवाज़ दें और इस तरह अपना दुख और नुकसान व्यक्त करें। [105] इन कथित कमियों के बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हटाए जाने के परिणाम और उन गवाहों के अनुभव वर्णित अनुसार ही हुए। [106] उनकी पीड़ा में पहचान की हानि, संस्कृति की हानि, शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण, और उसके बाद मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ, मानसिक चोट और दीर्घकालिक मानसिक बीमारी, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत और वित्तीय नुकसान हुआ। कई मामलों में, दुर्व्यवहार प्रणालीगत था, और बच्चों की देखभाल में या तो कोई बेहतर स्थिति नहीं थी [107] या बदतर स्थिति थी, जैसा कि *ट्रेवोरो ने* प्रदर्शित किया है।

हालाँकि, निष्कासन, दुर्व्यवहार और मुकदमेबाजी के बीच देरी के कारण, किसी भी वादी को सबूत के बोझ को पूरा करने में कठिनाई होगी। इसका एक कारण गवाहों की बीच में मृत्यु या गायब होना या उनकी याददाश्त का मिट जाना है। दूसरा कारण दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है। जबकि कई आदिवासी बच्चों को निष्कासन का समर्थन करने या उसे स्पष्ट करने के लिए दस्तावेजों के बिना ले जाया गया था, [108] रिकॉर्ड की कमी आदिवासी बच्चों के लिए अद्वितीय नहीं है। [109]

एक दृष्टिकोण से, यदि सरकार की नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ स्पष्ट रूप से नस्लवादी और नरसंहारकारी थीं, तो कोई लिखित सबूत की अपेक्षा की जानी चाहिए। अन्यथा, नस्लवाद का आरोप केवल अटकलें होंगी। इस दृष्टिकोण को ओ'लॉघलिन जे ने खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा:

> [साक्ष्य चोरी की गई पीढ़ी के अस्तित्व से इनकार नहीं करते हैं और कुछ सबूत थे कि कुछ भाग आदिवासी बच्चों को उनके माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध संस्थानों में ले जाया गया था। हालाँकि, मैं इन कार्यवाहियों में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर निष्कर्ष निकालने तक ही सीमित हूँ; वह साक्ष्य इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि आवेदकों द्वारा आरोपित भाग-आदिवासी बच्चों को हटाने की कोई नीति थी; और यदि, उस निष्कर्ष के विपरीत, ऐसी कोई नीति थी, तो इन कार्यवाहियों में साक्ष्य इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएंगे कि इन आवेदकों के संबंध में इसे कभी भी स्वाभाविक रूप से लागू किया गया था। [110]

कोई भी रिकॉर्ड आमतौर पर संस्थागत दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। नस्लवादी तर्क को आमतौर पर नस्लवादी निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है, [111] और सरकारी रिकॉर्ड में इसके बजाय हटाने के लिए 'सर्वोत्तम हित' कारणों को शामिल करने की संभावना होगी। [112] इन कठिनाइयों में सबसे ऊपर आधिकारिक दस्तावेजों की नियमितता की धारणा है, जो *क्यूबिलो* में अधिकांश दावों के लिए घातक थी । [113] यह साक्ष्य संबंधी धारणा अदालत को विपरीत साक्ष्य के अभाव में आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण की शुद्धता को मानने की अनुमति देती है।

विलियम्स और क्यूबिलो में पीटर गनर के मामलों में , माता-पिता की सहमति की वैधता के न्यायालयों के निष्कर्ष ने कार्रवाई के कई संभावित कारणों को समाप्त कर दिया, जैसे कि अतिक्रमण और गलत कारावास। *क्यूबिलो* में , ओ'लॉघलिन जे ने पीटर गनर की माँ के अंगूठे के निशान को उसके निष्कासन के लिए सहमति के रूप में स्वीकार करते हुए यह मान लिया कि 'यह कल्पना के दायरे से परे नहीं है कि एक समर्पित, अच्छे इरादे वाले गश्ती अधिकारी के लिए टॉपसी जैसे आदिवासी आदिवासी को दस्तावेज़ का अर्थ और प्रभाव समझाना संभव था'। [114]

ऐसी धारणाएँ [115] 'निष्कासन के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ' को नज़रअंदाज़ करती हैं, कि आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अक्षम निर्णय निर्माताओं के रूप में माना जाता था:

> प्रत्येक राज्य में, संबंधित अधिनियमों ने ऐसी व्यवस्थाएँ बनाईं जो स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती थीं। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोग अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में अक्षम थे। फिर भी यह माना गया कि अन्यथा अक्षम व्यक्ति राज्य को अपने बच्चे की कस्टडी देने की सहमति दे सकता है। [116]

स्वदेशी संस्कृतियों में मौखिक परंपरा प्राथमिक ऐतिहासिक पद्धति है। जबकि कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि अदालतों ने लिखित साक्ष्य को प्राथमिकता दी है, जो 'शाही संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा' है, [117] यह आलोचना आम कानून परीक्षणों में पारंपरिक रूप से दिए गए साक्ष्य की मौखिक प्रकृति की अनदेखी करती है। [118] एक अधिक वैध चिंता आदिवासी गवाहों और प्रमुख संस्कृति और इसकी कानूनी प्रणाली के सदस्यों के बीच भाषा, संस्कृति और संचार में अंतर से संभावित गलतफहमियाँ हैं। [119] यह वास्तविक संभावित अन्याय का मामला है, और चोरी की पीढ़ियों के मामलों में दिए गए साक्ष्य के भाषाई और समाजशास्त्रीय विश्लेषण का उपयोग करके आगे की खोज की जानी चाहिए। [120]

सी प्रक्रियागत बाधाएं

चोरी की पीढ़ियों के सदस्यों द्वारा सफल मुकदमेबाजी के लिए मुख्य प्रक्रियात्मक बाधा सीमाओं का क़ानून है। [121] जहां समय सीमा समाप्त हो गई है, और बचाव पक्ष सीमाओं के क़ानून पर निर्भर करता है, कानून समय के विस्तार की अनुमति देता है यदि ऐसा करना उचित और तर्कसंगत है। [122] प्रासंगिक कारकों में देरी का कारण (प्रतिवादी ने देरी में किस हद तक योगदान दिया है, सहित), देरी के कारण प्रतिवादी द्वारा झेला गया पूर्वाग्रह, और झेली गई चोट की प्रकृति और कथित आचरण जिसके कारण यह हुआ, शामिल होंगे। देरी के लिए एक वैध और समझने योग्य स्पष्टीकरण भी प्रतिवादी के प्रति अन्यायपूर्ण पूर्वाग्रह को दूर नहीं कर सकता है यदि देरी काफी लंबी है। [123]

कार्यवाही शुरू करने में देरी की व्याख्या करना मुश्किल साबित होता है। यदि 1970 के दशक की शुरुआत तक आदिवासी बच्चों के खिलाफ प्रणालीगत दुर्व्यवहार और गलत काम होते रहे होते, तो उम्मीद की जाती कि पहला रिट 1994 से पहले जारी हो जाता। [124] *देरी को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। माबो* में महत्वपूर्ण फैसले के बाद चुराई गई पीढ़ियों के मुकदमेबाजी का प्रवाह शुरू हुआ । [125] इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस फैसले के बाद इस बारे में धारणा बदल गई कि कानूनी प्रणाली मूल शीर्षक दावों में अदालतों में आदिवासी वादी के साथ कैसे निपटती है। एक अन्य प्रमुख घटना 1994 में डार्विन में *गोइंग होम* [126] नामक सम्मेलन था जहां 600 से अधिक हटाए गए बच्चे अपने अनुभव और न्याय के लिए भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए थे। इस सम्मेलन ने राष्ट्रीय जांच और *उन्हें घर लाने की* रिपोर्ट को जन्म दिया,

डी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं

आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग करना एक व्यापक सामाजिक अन्याय के ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ। जिस परिस्थिति के कारण और कई मामलों में आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की खराब सामाजिक और आर्थिक स्थिति पैदा हुई, वह उपनिवेशीकरण और उसके परिणामस्वरूप आदिवासी आबादी का अशक्तीकरण था। [[127] यह अन्याय चोरी की पीढ़ियों की स्वदेशी लोगों के रूप में पहचान और उपनिवेशवादियों के साथ उनके संबंधों से जुड़ा हुआ है। इसने कुछ लोगों की मुकदमा लड़ने की क्षमता या इच्छा को बाधित किया हो सकता है:

> [उनके निष्कासन और उसके बाद की जीवन कहानियों को राष्ट्र-राज्य की सीमाओं के भीतर रहने की नीतियों, प्रथाओं और राजनीति द्वारा मध्यस्थ किया जाता है, जो बेदखली, हिंसा और कानूनी व्यवस्थाओं पर आधारित है, जिसने स्वदेशी लोगों को गैर-स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। परिणामस्वरूप, आपराधिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोजगार सहित सभी प्रमुख सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के अनुसार स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई काफी वंचित बने हुए हैं। [128]

मानसिक बीमारी, मादक द्रव्यों के सेवन, स्वास्थ्य समस्याओं, कम जीवन प्रत्याशा और खराब शिक्षा की उच्च दर सहित सामाजिक-आर्थिक कारक स्वदेशी समुदायों के भीतर बाल संरक्षण में चिंता का विषय बने हुए हैं। [129]

कुछ लोगों के लिए, उपनिवेशित लोगों के सदस्य के रूप में मुकदमा करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है, [130] जो मुकदमेबाजी की कमी को समझाने के लिए कुछ हद तक जाता है। [131] यौन शोषण के पीड़ितों द्वारा यौन अपराधों की रिपोर्ट करने में देरी करने और सरकार द्वारा प्रणालीगत नस्लवादी आचरण के माध्यम से पीड़ित होने की रिपोर्ट करने में देरी या रिपोर्ट करने में विफलता के कारणों के बीच एक सादृश्य खींचा जा सकता है। यह न केवल चुराए गए पीढ़ी के सदस्यों पर लागू होता है, जिनका यौन शोषण किया गया था, बल्कि सभी के लिए, उनके और सरकार के बीच के रिश्ते के कारण, जिन्होंने उन्हें हटा दिया, और आगामी आघात और शर्म के कारण। [132] पीड़ितों को महसूस होने वाली शर्म और अपमान मुकदमेबाजी के लिए एक शक्तिशाली भावनात्मक हतोत्साहन हो सकता है। [133] यह तब और बढ़ जाता है जब पीड़ित का कानून के साथ पहले का नकारात्मक अनुभव रहा हो। [134

कानूनी कार्यवाही पहले से मौजूद आघात के संदर्भ में भी होती है, साथ ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक असंतुलन और औपनिवेशिक अन्याय, [135] और 'आध्यात्मिक उत्पीड़न' की व्यापक भावना भी होती है। [136] यह सब आदिवासी लोगों की अपने दावों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने, मध्यस्थता और मुकदमेबाजी के माध्यम से मुकदमा चलाने की इच्छा और क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह ऐसे समझौते भी पैदा कर सकता है, जो जनता के ध्यान में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी-जनरल की 2009 की रिपोर्ट, *फेडरल सिविल जस्टिस सिस्टम में न्याय तक पहुंच के लिए एक रणनीतिक ढांचा* , न्याय तक पहुंच टास्कफोर्स ने नोट किया: 'स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई कानूनी घटनाओं के जवाब में कोई कार्रवाई नहीं करने वाले समूह थे, ऐसा 50.9 प्रतिशत कानूनी घटनाओं के लिए किया गया, जबकि गैर-स्वदेशी लोगों के लिए यह 32 प्रतिशत था।' [137]

विंडशटल का अनुमान है कि चोरी की पीढ़ी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालतों के पंखों में मानवाधिकार वकीलों की एक सेना प्रतीक्षा कर रही है। इस सुझाव से उनका तात्पर्य है कि मुकदमेबाजी की लागत अदालत में चोरी की पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा नहीं है। हो सकता है कि कुछ वकीलों ने इन मामलों में तैयारी करने और पेश होने के लिए अपना समय स्वेच्छा से दिया हो। दूसरी ओर, टिप्पणीकारों ने उल्लेख किया है कि कैसे 'मामलों ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी संगठनों के महत्वपूर्ण संसाधनों का उपभोग किया है'। [138] चोरी की पीढ़ी के सदस्यों को कानूनी सहायता की उपलब्धता और लागत, अतीत और भविष्य दोनों में, एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है, न कि केवल अटकलों की।

ई क्षतिपूर्ति की अपर्याप्तता

मुकदमेबाजों को केवल या मुख्य रूप से पैसे से प्रेरित नहीं किया गया है। ओ'लॉघलिन जे ने कहा कि उन्होंने 'ऐसे किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया कि कोई भी आवेदक मुकदमेबाजी के पैसे की तलाश में है।' [139] कभी-कभी पीड़ित को मौद्रिक मुआवज़ा पर्याप्त मुआवज़ा नहीं लगता है, जबकि आघात से उबरने की ज़रूरत होती है और उनके दिमाग में माफ़ी और अपनी पीड़ा को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। [140] मुआवज़ा और गलत काम के लिए सार्वजनिक न्यायिक औचित्य आघात से उबरने में मदद कर सकता है और पीड़ित को उस स्थिति में रखना शुरू कर सकता है जिसमें वे अन्यथा होते, लेकिन जैसा कि एटकिंसन जे ने नोट किया है, 'आखिरकार, बचपन के नुकसान, पारिवारिक संबंधों के नुकसान और आत्म-पहचान के नुकसान को सुधारने का कोई तरीका नहीं है।' [141] इसके अलावा, हटाए गए बच्चे की अपने बच्चों से प्रभावी ढंग से संबंध बनाने में असमर्थता के माध्यम से हटाए जाने के अंतर-पीढ़ीगत प्रभावों के लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। [142]

कार्य-कारण संबंधी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या नुकसान हुआ है, और यह कब हुआ। क्या नुकसान हटाए जाने के कारण हुआ या देखभाल के दौरान या देखभाल से मुक्त होने के बाद दुर्व्यवहार के कारण हुआ? *विलियम्स में इस बात पर जोर दिया गया था।* [143] *क्यूबिलो* में , जे ओ'लफलिन ने आवेदकों को हुए नुकसान और आघात के लिए उनके हटाए जाने को - और इससे जुड़ी संस्कृति, भाषा, पारिवारिक संबंधों और भूमि से जुड़ाव की हानि को - जिम्मेदार ठहराया, जिसके लिए आदिवासी मामलों के निदेशक उत्तरदायी नहीं थे, न कि देखभाल में उनके साथ किए गए व्यवहार को। [144] ट्रेवोर *में* विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया , जहां न्यायालय ने स्वीकार किया कि हटाए जाना ही नुकसान का एक बड़ा कारण था। ब्रूस ट्रेवोर को व्यक्तिगत चोट और नुकसान के लिए 450,000 डॉलर का हर्जाना दिया गया , जिसमें उनकी आदिवासी संस्कृति की हानि भी शामिल थी वर्ष 2007 के बाद से ही न्यायालयों ने इतनी ऊंची संख्या को स्वीकार किया है।

क्यूबिलो में , जे ओ'लफलिन ने संस्कृति के नुकसान के लिए राशि सहित हर्जाने की काल्पनिक मात्रा का अनुमान लगाया, लेकिन वादी द्वारा कम करने में विफलता के कारण इसे कम कर दिया, [148] लोर्ना क्यूबिलो को $110 000 प्लस $16 800 ब्याज और पीटर गनर को $125 000 प्लस $19 800 प्रदान किए। *विलियम्स* में जे अबादी ने 'आकस्मिक' मात्रा का अनुमान लगाया, [149] जिसमें से केवल आधा सामान्य हर्जाना था, दूसरा आधा पिछले आर्थिक नुकसान के लिए विशेष हर्जाना था, जो $100 000 प्लस ब्याज (गणना नहीं की गई) था। इन राशियों की आलोचना की गई है कि ये समान परिस्थितियों में गैर-आदिवासी दावेदारों के लिए दिए गए आदेशों की तुलना में काफी कम हैं [150] *और ट्रेवोर* निर्णय से पहले , जरूरी नहीं कि ये मुकदमा करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करें।

चतुर्थ निष्कर्ष

मुकदमेबाजी की कमी ऐतिहासिक गलत कामों के बारे में बहुत कम बताती है। कई कारक किसी पक्ष की इच्छा या क्षमता को प्रभावित करते हैं, और विशेष रूप से चोरी की पीढ़ियों के एक सदस्य को, मुकदमा करने और अदालत में सबूत पेश करने के लिए। *ब्रिंगिंग देम होम* रिपोर्ट ने ऐसे कई हतोत्साहन को पहचाना, [151] और एक मुआवजा निधि बोर्ड के माध्यम से क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा। इसका दृष्टिकोण क्षतिपूर्ति के साथ अधिक समग्र रूप से निपटता है, उदाहरण के लिए गैर-पुनरावृत्ति की प्रतिबद्धताओं को शामिल करके।

हालांकि नरसंहार के बारे में बहस जारी है, [152] अदालतों ने कानून निर्माताओं और प्रशासकों के लाभकारी इरादे को स्वीकार किया है, हालांकि वर्तमान मानकों के आधार पर यह गुमराह करने वाला है। जबकि नस्लीय भेदभाव का आरोप उचित हो सकता है, [153] व्यवहार को उस समय के मानकों के आधार पर आंका जाना चाहिए। नस्लीय भेदभाव में नैतिक और न्यायशास्त्रीय क्रांति ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 1960 के दशक के अंत तक नहीं हुई थी, जब 1967 में *आदिवासी अधिकारों पर संवैधानिक जनमत संग्रह हुआ था* , और 1970 के दशक की शुरुआत में 1971 में आदिवासी ध्वज के डिजाइन के साथ, [154] 'बहुसंस्कृतिवाद' का जन्म, गैर-भेदभावपूर्ण आव्रजन सुधार, *नस्लीय भेदभाव अधिनियम 1975* (Cth) का अधिनियमन , [155] और 1970 के दशक के अंत में नए 'आदिवासी बच्चों के लिए प्लेसमेंट सिद्धांतों' का विकास हुआ। [156] वर्तमान मानकों के आधार पर स्टोलन जेनरेशन को हटाने का निर्णय लेना उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने उस समय काम किया था। इस तरह का दृष्टिकोण वर्तमान में स्वीकार्य सभी आचरण को अप्रत्याशित भविष्य के नागरिक दावों या यहां तक कि आपराधिक आरोपों के लिए खोल देगा यदि मानक बदल जाते हैं। *ट्रेवोरो* में भी , उस समय के मानकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। [157] हालाँकि, हाल ही में हटाए गए जितने अधिक होंगे, वे उतने ही कम स्वीकार्य होंगे, यदि पर्याप्त गैर-नस्लीय कारणों के बिना किए गए हों।

तो जाहिर है, चोरी की पीढ़ियों के मुकदमे में कानूनी बाधाएं हैं, लेकिन कई वादियों के लिए बाधाएं मौजूद हैं। चोरी की पीढ़ी के सदस्यों को मुआवज़ा देने के लिए एक मजबूत नैतिक तर्क है। [158] हालांकि, भविष्य में पूछे जाने वाले सवाल यह हैं कि क्या इसे प्राप्त करने में कानूनी बाधाएं प्रणालीगत हैं या चोरी की पीढ़ियों के मामलों की प्रकृति में निहित हैं, और क्या ये परिस्थितियाँ भविष्य में न्यायिक या विधायी हस्तक्षेप की मांग करती हैं। उन्हें तत्काल उत्तर की आवश्यकता है

---

[*] एलएलबी (ऑनर्स) एलएलएम; मोनाश यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में विक्टोरियन बैरिस्टर और सत्रवार अकादमिक। वह पारिवारिक कानून, आपराधिक कानून और बच्चों के न्यायालय में अभ्यास करते हैं, और कानून और मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए केंद्र में वर्तमान एसजेडी उम्मीदवार हैं। लेखक इस पेपर के पहले संस्करण पर अपनी टिप्पणियों के लिए पाउला गेरबर को धन्यवाद देना चाहते हैं।

[1] ए.ओ. नेविल, चीफ प्रोटेक्टर ऑफ एबोरिजिन्स (डब्लू.ए.) (21 अक्टूबर 1931) डोरिस पिल्किंगटन में उद्धृत, *फॉलो द रैबिट-प्रूफ फेंस* (क्वींसलैंड विश्वविद्यालय प्रेस, 1996) 126.

[2] अन्ना हैबिच, *ब्रोकन सर्किल्स: फ़्रेगमेंटिंग इंडिजिनस फ़ैमिलीज़ 1800–2000* (फ़्रेमेंटल आर्ट्स सेंटर प्रेस, 2000) 130.

[3] उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार और समान अवसर आयोग, आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर बच्चों को उनके परिवारों से अलग करने की राष्ट्रीय जांच, *उन्हें घर लाना* (1997) 217, 'दो व्यापक अवधियाँ' (' *उन्हें घर लाना* ')। आयुक्त कभी भी 'चोरी पीढ़ी' शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह लेबल इतिहासकार पीटर रीड द्वारा 1981 में स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के एक सीमित समूह के संदर्भ में गढ़ा गया था, *स्टोलन जेनरेशन: द रिमूवल ऑफ़ आदिवासी बच्चों इन न्यू साउथ वेल्स 1883 से 1969* (आदिवासी मामलों का मंत्रालय (NSW), 6 वां संस्करण, 2007)।

[4] उदाहरण के लिए, कीथ विंडशटल में चर्चा देखें। *द फैब्रिकेशन ऑफ एबोरिजिनल हिस्ट्री वॉल्यूम 3: द स्टोलन जेनरेशन 1881–2008* (मैकलि प्रेस, 2009) अध्याय 13. इसकी तुलना रॉबर्ट मैन की आलोचना, 'कमेंट' (2010) 53 *द मंथली* 8 और कीथ विंडशटल की प्रतिक्रिया, 'मैन वास्तविक बहस से बचते हैं' (2010) 54(5) *क्वाड्रेंट* 60 से करें। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, 'एकेडमिक्स डिबेट कंटेंट्स ऑफ स्टोलन जेनरेशन रिपोर्ट' *7:30 रिपोर्ट* , 29 मार्च 2001, < http://www.abc.net.au/7.30/stories/s268644.htm > रॉन ब्रंटन, 'बेट्रेइंग द विक्टिम: द स्टोलन जेनरेशन रिपोर्ट' (1998) 10(1) *आईपीए बैकग्राउंडर* 4 भी देखें; रॉबर्ट मैन, 'इन डेनियल: द स्टोलन जेनरेशन्स एंड द राइट' *क्वार्टरली एसे इश्यू 1* (ब्लैक इंक, 2001); डी पेरी, 'डेबंकिंग विंडशटल की इतिहास की सौम्य व्याख्या' *क्राइकी* पर (12 फरवरी 2008) < http://www.crikey.com.au/2008/02/12/debunking-windschuttles-benign-interpretation-of-history/ > पीटर रीड, 'डोंट लेट द फैक्ट्स स्पॉयल दिस कैंपेन', *द ऑस्ट्रेलियन* (सिडनी) 18 फरवरी 2008; जस्टिस रोसलिन एटकिंसन, 'डेनियल एंड लॉस: द रिमूवल ऑफ इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर फैमिलीज' [2005] QUTLawJJl 4 ; (2005) 5(1) *क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लॉ एंड जस्टिस जर्नल* 71 , 73.

[5] मुख्य विवाद आदिवासी लोगों को खत्म करने के लिए कथित नरसंहार या नस्लीय इरादे से जुड़ा है। सर रोनाल्ड विल्सन ने स्वीकार किया कि उन्हें *ब्रिंगिंग देम होम* में 'नरसंहार' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था , क्योंकि इससे निष्कासन के परिणामों के

बजाय इरादे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित होता है: पैट्रिक कार्लियन, 'व्हाइट लाइज़', *द बुलेटिन* (सिडनी) 12 जून 2001, 26–30, 27.

[6] *उन्हें घर लाना* , उपरोक्त एन 3, 231.

[7] वही 241.

[8] विंडशटल, उपरोक्त एन 4, 17.

[9] वही 571.

[10] वही। चोरी की पीढ़ियों के लिए अपनी माफ़ी में, पूर्व प्रधान मंत्री केविन रुड ने 1910 और 1970 के बीच '50 000 तक' का हवाला दिया: राष्ट्रमंडल, *संसदीय बहस* , प्रतिनिधि सभा, 13 फरवरी 2008, 169 (केविन रुड, प्रधान मंत्री)।

[11] विंडशटल, उपरोक्त एन 4, 617, तालिका 13.1. संभावित वादियों के समूह के रूप में 50,000 से 100,000 के बीच के आंकड़ों की पहचान करना उनके लिए बेईमानी प्रतीत होती है, जब अगले अध्याय में वे चोरी किए गए बच्चों की वास्तविक संख्या को उच्च आंकड़े के 10 प्रतिशत से भी कम होने का अनुमान लगाते हैं।

[12] कॉलिन बॉर्के और बिल एडवर्ड्स, 'परिवार और रिश्तेदारी' कॉलिन बॉर्के, एलेनोर बॉर्के और बिल एडवर्ड्स (संपादक), *एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया* (क्वींसलैंड प्रेस विश्वविद्यालय, दूसरा संस्करण , 1994) 100, 101–2.

[13] वास्तव में, भुगतान ब्याज के बदले में किया गया था। लागत और ब्याज पर निर्णय देखें: *ट्रेवोर बनाम स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया (नंबर 6)* [2008] एसएएससी 4 (1 फरवरी 2008) (ग्रे जे) (*'ट्रेवोर'*)।

[14] विंडशटल, उपरोक्त एन 4, 571.

[15] वही 572.

[16] वही.

[17] *माबो बनाम क्वींसलैंड (नंबर 2)* [1992] एचसीए 23 ; (1992) 175 सीएलआर 1 (*'माबो'*)।

[18] *विक पीपल्स बनाम क्वींसलैंड* (1996) 187 सीएलआर 1.

[19] *उदाहरण के लिए, ब्रिंगिंग देम होम* , उपरोक्त एन 3, 241 सेऊपर दिया गया उद्धरण देखें

[20] राष्ट्रमंडल, *संसदीय बहस* , प्रतिनिधि सभा, 13 फरवरी 2008 (केविन रुड, प्रधानमंत्री) 167. विशेष रूप से 170 पर, प्रधानमंत्री ने क़ानून और प्रत्यायोजित विधान द्वारा दी गई शक्तियों का उल्लेख किया है, जिसने बच्चों को नस्ल के आधार पर हटाना वैधानिक बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वे कानून थे जिनके कारण 'चोरी की गई पीढ़ियाँ संभव हुईं।'

[21] एंटोनियो बूटी, 'स्वदेशी बच्चों को उनके परिवारों से हटाना: मुकदमेबाजी का रास्ता' (1998) *यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लॉ रिव्यू* 203 , 206।

[22] बॉर्के और एडवर्ड्स, उपरोक्त एन 12, 114–16.

[23] जूली कैसिडी, ' *क्यूबिलो और गनर बनाम द कॉमनवेल्थ* : ए डेनियल ऑफ द स्टोलन जेनरेशन' [2003] ग्रिफ़लॉरव 5 ; (2003) 12(1) *ग्रिफ़िथ लॉ रिव्यू* 114 , 124–5.

[24] पाम ओ'कॉनर, 'हिस्ट्री ऑन ट्रायल: *क्यूबिलो और गनर बनाम द कॉमनवेल्थ ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया* ' [2001] ऑल्टलॉज 17 ; (2001) 26(1) *अल्टरनेटिव लॉ जर्नल* 27 , 30; रोज़ेन कैनेडी, 'स्टोलन जेनरेशन टेस्टिमनी: ट्रॉमा, हिस्टोरियोग्राफी, एंड द क्वेश्चन ऑफ़ "ट्रुथ"' (2001) 25 *एबोरिजिनल हिस्ट्री* 116; क्रिस क्यूनेन और जूलिया ग्रिक्स, *द लिमिटेशन्स ऑफ़ लिटिगेशन इन स्टोलन जेनरेशन केसेज* (ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ एबोरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर स्टडीज़, 2004) 26.

[25] *व्हाइटहॉर्न बनाम आर* [1983] एचसीए 42 ; (1983) 152 सीएलआर 657 , [33] (डॉसन जे), *आर बनाम एपोस्टिलिडेस* [1984] एचसीए 38 में पांच न्यायाधीशों के संयुक्त निर्णय में उच्च न्यायालय के बहुमत द्वारा अनुमोदित; (1984) 154 सीएलआर 563 , [15]।

[26] एटकिंसन, उपरोक्त एन 4, 87.

[27] इसे *क्यूबिलो बनाम द कॉमनवेल्थ (नंबर 2)* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 41 में ओ'लफलिन जे द्वारा मान्यता दी गई थी। *नुल्यारिम्मा बनाम थॉम्पसन* [1999] एफसीए 1192 ; (1999) 96 एफसीआर 153 में 173-174 परमर्केल जे की टिप्पणियों को भी देखें , *जिसे क्यूबिलो* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 34 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। दूसरी ओर, न्यायालय अक्सर विवादास्पद क्षेत्र में एक नए दायित्व को मान्यता देकर, या किसी विशेष दिशा में सामान्य कानून के विकास को स्वीकार करके न्याय प्रदान करते हैं। इस अर्थ में एक नए कर्तव्य को मान्यता देने का विकल्प एक राजनीतिक, कानून बनाने के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

[28] रिचर्ड ब्रूम, *एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन्स: ए हिस्ट्री सिंस 1788* (एलन एंड अनविन, चौथा संस्करण , 2010), 311.

[29] वही.

[30] वही 316.

[31] *क्रूगर बनाम द कॉमनवेल्थ* [1997] एचसीए 27 ; (1997) 190 सीएलआर 1 (' *क्रूगर* ')।

[32] 1925 और 1949 के बीच उत्तरी क्षेत्र में आदिवासी लोगों के मुख्य संरक्षक, जो बाद में मूल निवासी मामलों के निदेशक बने, ने *आदिवासी अध्यादेश 1918* (एनटी) के अनुसार लोगों को हटाया था। अध्यादेश ने मुख्य संरक्षक को आदिवासी लोगों की देखभाल, हिरासत या नियंत्रण करने की अनुमति दी, जहाँ उनकी राय में यह उनके हित में था (धारा 6), उन्हें पहले हर आदिवासी व्यक्ति और हर 'अर्ध-जाति' बच्चे का कानूनी अभिभावक बनाया, और बाद में सभी आदिवासी लोगों का (धारा 7)। मुख्य संरक्षक को किसी भी आदिवासी या 'अर्ध-जाति' को आदिवासी रिजर्व या संस्थान में हटाने और उसे वहाँ रखने की अनुमति थी (धारा 16)। अध्यादेश (धारा 67) के अनुसार बनाए गए नियमों के तहत, सभी संरक्षकों को समान रूप से सशक्त बनाया गया था।

[33] *इसे कल्याण अध्यादेश 1953* (एनटी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, हालांकि मई 1957 में इसे निरस्त कर दिया गया था।

[34] *क्रूगर* [1997] एचसीए 27 ; (1997) 190 सीएलआर 1 , 41 (ब्रेनन सीजे), 53 (डॉसन जे), 79 (टूही जे), 104 (गॉड्रॉन जे), 141 (मैकह्यू जे), 161 (गुम्मो जे)।

[35] वही 45 (ब्रेनन सी.जे.), 62 (डॉसन जे.), 85 (टूही जे.), 111 (गॉड्रॉन जे.), 144 (मैकह्यू जे.), 162 (गुम्मो जे.)। ब्रेनन सी.जे., डॉसन और मैकह्यू जे.जे. ने माना कि इस सिद्धांत का उत्तरी क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टूही, गममो और गॉड्रॉन जे.जे. ने माना कि यह सिद्धांत लागू तो होता है, लेकिन इसका उल्लंघन नहीं होता क्योंकि कानून न्यायिक शक्ति प्रदान नहीं करता, बल्कि आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए प्रशासनिक शक्ति प्रदान करता है।

[36] वही 40 (ब्रेनन सी.जे.), 87 (टूही जे.), 176 (गुम्मो जे.)। डॉसन, मैकह्यू और गॉड्रॉन जे.जे. ने इस सवाल का फैसला नहीं किया, हालांकि 60-1 पर डॉसन जे., जिनके साथ मैकह्यू जे. इस बिंदु पर सहमत थे, ने कहा कि यदि धारा 116 लागू होती, तो माननीय न्यायाधीश गुम्मो जे. के साथ सहमत होते कि परिस्थितियों में इसका उल्लंघन नहीं किया गया था।

[37] वही 45 (ब्रेनन सी.जे.), 70 (डॉसन जे.), 142 (मैकह्यू जे.) 157 (गुम्मो जे.)। टूही जे. ने 93 पर माना कि कानून इस तरह के अधिकार द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन *क्रूगर* में मुकदमे से पहले ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है , क्योंकि इस पर तर्क दिया गया है। गॉड्रॉन जे. ने 130 पर पाया कि इस अधिकार के उल्लंघन के कारण अध्यादेश के कुछ हिस्से अमान्य हैं।

[38] वही 44–5 (ब्रेनन सी.जे.), 68 (डॉसन जे.), 114, (गॉड्रॉन जे.), 155 (गुम्मो जे.)। टूही जे. ने 97 पर इस प्रश्न को खुला छोड़ दिया। मैकह्यू जे. इस बिंदु पर चुप रहे।

[39] वही 46 (ब्रेनन सी.जे.), 93 (टूही जे.), 125–126 (गॉड्रॉन जे.)। डॉसन और मैकह्यू जे.जे. को इस मुद्दे पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी। 148 पर गममो जे. ने एक नए कारण की दलील देने की चुनौतियों को देखा, लेकिन मामले पर निर्णय लेने से भी इनकार कर दिया। (किसी भी न्यायाधीश ने इक्विटी में दावों की संभावना का उल्लेख नहीं किया।)

[40] वही 70–1 (डॉसन जे), 88 (टूही जे), 107 (गॉड्रॉन जे), 144 (मैकह्यू जे), 158-189 (गुम्मो जे)।

[41] हालांकि, डॉसन जे ने माना कि उत्तरी क्षेत्र में ऐसी कोई निहित स्वतंत्रता नहीं थी: ibid 72–3। इसके विपरीत, गॉड्रॉन जे ने 107 पर संभावना की पहचान की, हालांकि इस बिंदु पर निर्णय नहीं लिया, कि संविधान की *धारा* 122 में'सामान्य कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत मानवाधिकारों और सम्मान के घोर उल्लंघन को अधिकृत नहीं करता है'।

[42] *क्रूगर* [1997] एचसीए 27 ; (1997) 190 सीएलआर 1 , 36 (ब्रेनन सीजे)।

[43] वही 36–7 (ब्रेनन सी.जे.)। 52–3 (डॉसन जे.) भी देखें।

[44] एम शेफ़र, 'क्रूगर और ब्रे के बाद की चोरी की पीढ़ियाँ' [1998] यूएनएसडब्ल्यूलॉज 1 23 ; (1998) 21(1) *यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स लॉ जर्नल* 247.

[45] *क्यूबिलो बनाम द कॉमनवेल्थ [संख्या 2]* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 (' *क्यूबिलो*')। आवेदकों के पक्ष में निर्णय के कुछ पहलुओं को अपील पर उलट दिया गया था, लेकिन सभी प्रतिकूल निष्कर्षों की पुष्टि की गई थी: *क्यूबिलो बनाम द कॉमनवेल्थ* [2001] एफसीए 1213 ; (2001) 112 एफसीआर 455 (पूर्ण न्यायालय)।

[46] वही 362–3. यह मामला उत्तरी क्षेत्र में 2000 से अधिक संभावित आवेदकों के लिए एक परीक्षण मामला था: मार्क चैंपियन, 'पोस्ट- *क्रूगर* : व्हेयर टू नाउ फॉर द स्टोलन जेनरेशन?' [1998] इंडिग्लॉबी 45 ; (1998) 4(12) *स्वदेशी कानून बुलेटिन* 9.

[47] वही 443–5.

[48] *क्यूबिलो बनाम द कॉमनवेल्थ* [1999] एफसीए 518 ; (1999) 89 एफसीआर 528 (ओ 'लफलिन जे, सारांश बर्खास्तगी आवेदन)।

[49] वही 103–8; 358.

[50] वही 408. यह परिणाम था, लेकिन आवेदकों के संबंध में उद्देश्य नहीं था।

[51] वही 483.

[52] वही 358–60.

[53] माता-पिता की सहमति के संबंध में भाग III बी (साक्ष्य संबंधी बाधाएं) के अंतर्गत नीचे देखें

[54] वही 367–8.

[55] वही 369.

[56] वही 397.

[57] वही.

[58] वही.

[59] वही.

[60] *विलियम्स बनाम मिनिस्टर, आदिवासी भूमि अधिकार अधिनियम 1983 [संख्या 1]* (1994) 35 एनएसडब्ल्यूएलआर 497 देखें

[61] *विलियम्स बनाम मिनिस्टर, आदिवासी भूमि अधिकार अधिनियम 1983 [संख्या 2]* [1999] एनएसडब्ल्यूएससी 843 ; (1999) 25 फैम एलआर 86 (' *विलियम्स*')।

[62] जबकि न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विलियम्स चोरी की पीढ़ियों की सदस्य नहीं थी [5], क्योंकि उसकी माँ ने अनुरोध किया था कि उसे हटा दिया जाए, मामले की परिस्थितियाँ चोरी की पीढ़ियों के सदस्यों के लिए प्रासंगिक हैं।

[63] वही [672]–[764].

[64] वही [675]–[694].

[65] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 15.

[66] *विलियम्स* [1999] एनएसडब्ल्यूएससी 843 ; (1999) 25 फैम एलआर 86 , [695]–[756]।

[67] वही [757]–[824].

[68] वही [825]–[845].

[69] वही [846]–[865].

[70] वही [786]। अपील की अदालत ने इस चिंता पर जोर दिया: *विलियम्स बनाम मंत्री, आदिवासी भूमि अधिकार अधिनियम 1983 [संख्या 3]* (2000) ऑस्ट टॉर्ट्स रिपोर्ट 81-578 , [162]।

[71] *विलियम्स* [1999] एनएसडब्ल्यूएससी 843 ; (1999) 25 फैम एलआर 86 , [820]–[823]।

[72] इस कार्रवाई के कारण की संभावना को पहले ही पहचान लिया गया था: पॉल बैटले, 'चोरी हुए बच्चों के प्रति राज्य का प्रत्ययी कर्तव्य' [1996] एयूजेएलएचराइट्स 3 ; (1996) 2(2) *ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स* 177 ; बूटी, उपरोक्त एन 21, 210-15; मेलिसा अब्राहम्स, 'चोरी हुई पीढ़ी के संबंध में प्रत्ययी कर्तव्य के उपयोग पर एक वकील का परिप्रेक्ष्य' [1998] यूएनएसडब्ल्यूलॉजेएल 18 ; (1998) 21(1) *यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स लॉ जर्नल* 213 ; टिम हैमंड, '"चोरी हुई पीढ़ी" - एक प्रत्ययी कर्तव्य की खोज' (1998) 5(2) *मर्डोक यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ़ लॉ* 14 ; अमांडा जोन्स 'द स्टेट एंड द स्टोलन जेनरेशन: रिकॉग्नाइजिंग ए फिड्यूशरी ड्यूटी' [2002] मोनाशयूलॉरव 3 ; (2002) 28(1) *मोनाश यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू* 59. समय विस्तार के आवेदन में, *जॉनस्टन बनाम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज* [1999] NSWSC 1156 (2 दिसंबर 1999) [136] (' *जॉनस्टन*') में रॉल्फ जे ने माना कि किसी मामले की परिस्थितियाँ भविष्य में फिड्यूशरी ड्यूटी के उल्लंघन से मुआवज़े को जन्म दे सकती हैं। हालाँकि, *ट्रेवरो* [2008] SASC 4 (1 फरवरी 2008) में ग्रे जे के पहले उदाहरण में इस कार्रवाई के पक्ष में निर्णय को अपील पर उलट दिया गया था।

[73] [1999] एनएसडब्ल्यूएससी 843 ; (1999) 25 फैम एलआर 86 , [733] लेकिन [755] में भी, हालांकि वहां तर्क लापरवाही (देरी और पूर्वाग्रह से) पर आधारित था, जो एक अच्छा बचाव है, चाहे एक प्रत्ययी कर्तव्य मौजूद हो या नहीं।

[74] [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 408–9.

[75] *स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम लैम्पार्ड-ट्रेवोर* [2010] एसएएससी 56 (22 मार्च 2010) [342]।

[76] चोरी की पीढ़ियों के मुकदमे से संबंधित चोरी की मजदूरी की जांच और मुकदमेबाजी है, जहां प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन को मौद्रिक प्रकृति का होने का दावा किया गया था: ऑस्ट्रेलिया की संसद, कानूनी और संवैधानिक मामलों पर सीनेट की स्थायी समिति, *अधूरा काम: स्वदेशी चोरी की मजदूरी* , (2006) 123-6; रोजालिंड किड, *ट्रस्टीज़ ऑन ट्रायल: चोरी की मजदूरी की वसूली* (एबोरिजिनल स्टडीज प्रेस, 2006); सनुष्का मुदलियार, 'चोरी की मजदूरी और प्रत्ययी कर्तव्य - क्वींसलैंड में स्वदेशी श्रमिकों के लिए सरकार की जवाबदेही का कानूनी विश्लेषण' [2003] AUIndigLawRpr 33 ; (2003) 8(3) *ऑस्ट्रेलियाई स्वदेशी कानून रिपोर्टर* 1.

[77] [1999] एनएसडब्ल्यूएससी 1156 , [200]। हालाँकि, यह मामला अंतिम निर्णय तक नहीं पहुँचा।

[78] जेम्स प्लंकेट, 'नेगलीजेंस के साथ सावधानी बरतें' (2010) 86(5) *लॉ इंस्टीट्यूट जर्नल* 38.

[79] [2010] एसएएससी 56 (22 मार्च 2010)।

[80] [2007] एसएएससी 285 ; (2007) 98 एसएएसआर 136.

[81] वही [40].

[82] वही [47].

[83] वही [572]–[582].

[84] *स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम लैम्पार्ड-ट्रेवोर* [2010] एसएएससी 56 (22 मार्च 2010)।

[85] वही [266].

[86] वही [275].

[87] वही [409].

[88] वही.

[89] वही [388].

[90] वही [283].

[91] वही [307].

[92] वही [335]–[342].

[93] वही [276].

[94] वही [401]. उपरोक्त एन 87 भी देखें.

[95] रॉबर्ट मैन, 'जस्टिस ओ'लफलिन क्या नहीं देख पाए' रॉबर्ट मैन में, *लेफ्ट, राइट, लेफ्ट: पॉलिटिकल एसेज 1977–2005* (ब्लैक इंक, 2005) 207, 215; जेनेट रैन्सली और एलेना मार्केटी, 'ऑस्ट्रेलियाई कानून की छिपी सफेदी' [2001] ग्रिफ़लॉरव 9 ; (2001) 10 *ग्रिफ़िथ लॉ रिव्यू* 139 ; ट्रिश लूकर, 'सुलह के विमर्श में "उपनिवेशवाद के बाद" भूलने की बीमारी: चोरी की पीढ़ियों के प्रति कानून की प्रतिक्रिया में शून्यता' (2005) 22 *ऑस्ट्रेलियाई नारीवादी कानून जर्नल* 67 ; एलेना मार्केटी और जेनेट रैन्सले, 'अचेतन नस्लवाद: "चोरी पीढ़ी" मामलों में न्यायिक तर्क की जांच' (2005) 14(4) *सामाजिक और कानूनी अध्ययन* 533 , 542-547; एलिसन नेविल, ' *क्यूबिलो बनाम कॉमनवेल्थ* : क्लासिफाइंग टेक्स्ट एंड द वायलेंस ऑफ एक्सक्लूजन' [2005] MqLawJl 3 ; (2005) 5 *मैक्वेरी लॉ जर्नल* 31.

[96] मैन, 'जस्टिस ओ'लफलिन क्या नहीं देख पाए', उपरोक्त एन 95, 207, 215।

[97] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 5.

[98] एन कर्थोयस, एन जेनोवेस और अलेक्जेंडर रेली, *राइट्स एंड रिडेम्पशन: हिस्ट्री, लॉ एंड इंडिजिनस पीपल* (यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स प्रेस, 2008) 135; साइमन यंग, 'द लॉन्ग वे होम' [1998] यूक्यूलॉजएल 4 ; (1998) 20(1) *यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड लॉ जर्नल* 70 , 85. वही विकास या परिवर्तन, *माबो* से पहले मूल शीर्षक में हुआ , जैसे *मिलिरपम बनाम नोबेल्को* (1971) 17 एफएलआर 141 और *कोए बनाम द कॉमनवेल्थ* [1979] एचसीए 68 ; (1979) 53 एएलजेआर 403.

[99] हीथर मैकरै एट अल, *स्वदेशी कानूनी मुद्दे, टिप्पणी और सामग्री* (लॉबुक कंपनी, 4वां संस्करण, 2009) [11.390]।

[100] लारिसा बेहरेंड्ट, क्रिस क्यूनीन और टेरी लिब्समैन, *ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी कानूनी संबंध* (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009) 246–7।

[101] *न्युल्यारिम्मा बनाम थॉम्पसन* [1999] एफसीए 1192 ; (1999) 96 एफसीआर 153 ; *बज़ाकॉट बनाम हिल* [1999] एफसीए 639 ; डगलस गुइलफॉयल ' *न्युल्यारिम्मा बनाम थॉम्पसन* : क्या ऑस्ट्रेलिया में सामान्य कानून में नरसंहार एक अपराध है?' [2001] फेडलॉआरडब्ल्यू 1 ; (2001) 29 *संघीय कानून समीक्षा* 1 ; डेविड मार्कोविच, 'नरसंहार, एक अपराध जिसके लिए कोई एंग्लो-सैक्सन राष्ट्र दोषी नहीं हो सकता' (2003) 10(3) *मर्डोक यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ़ लॉ* 27.

[102] कार्लायन, उपरोक्त एन 5.

[103] वही.

[104] *मानवाधिकार और समान अवसर आयोग अधिनियम 1986* (सी.टी.एच.) धारा 21. इस कानून का नाम 2009 में बदलकर *ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1986* (सी.टी.एच.) कर दिया गया। ऐसी जांच जांच के संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत आती: *उन्हें घर लाना* , उपरोक्त एन 3, 2–3।

[105] कार्लायन में सर रोनाल्ड विल्सन का साक्षात्कार देखें, उपरोक्त एन 5, 27. सहायता और आगे के संसाधनों के लिए मामूली अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया: मैन, 'इन डेनियल: द स्टोलन जेनरेशन एंड द राइट', उपरोक्त एन 5, 74-5.

[106] *उन्हें घर लाने* के अलावा, ऑस्ट्रेलिया में कई जांचों और रिपोर्टों ने भी उन बच्चों के इलाज की जांच की है जिन्हें उनके परिवारों से हटा दिया गया है: देखें सीनेट सामुदायिक मामले संदर्भ समिति, ऑस्ट्रेलिया की संसद, *भूले हुए ऑस्ट्रेलियाई: बच्चों के रूप में संस्थागत या घर से बाहर देखभाल का अनुभव करने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर एक रिपोर्ट (2004*); लीन फोर्ड, *क्वींसलैंड संस्थानों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की जांच आयोग* (1999) ('फोर्ड जांच'); सीनेट सामुदायिक मामले संदर्भ समिति, ऑस्ट्रेलिया की संसद, *खोए हुए मासूम। रिकॉर्ड को सही करना: बाल प्रवास पर रिपोर्ट* (2001);रेक्स वाइल्ड और पेट्रीसिया एंडरसन, यौन दुर्व्यवहार से आदिवासी बच्चों के *संरक्षण की जांच बोर्ड , छोटे बच्चे पवित्र हैं* और सबसे हाल ही में लोकपाल विक्टोरिया की *बाल संरक्षण में स्वयं प्रस्ताव जांच - घर से बाहर देखभाल* (2010); तस्मानियाई लोकपाल, *बच्चों की बात सुनें' बच्चों के रूप में राज्य देखभाल में वयस्कों से दुर्व्यवहार के दावों की समीक्षा* (2004)।

[107] एटकिंसन, उपरोक्त एन 4, 81–3.

[108] उपरोक्त क्रमांक 3 पढ़ें।

[109] उदाहरण के लिए, क्वींसलैंड सरकार की *गुमशुदा टुकड़े: बच्चों के संस्थानों के पूर्व निवासियों को रिकॉर्ड तक पहुँचने में सहायता के लिए सूचना* (2001) देखें।

[110] *क्यूबिलो* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 358।

[111] बेहरेंड्ट, क्यूनीन और लिब्समैन, एन 100 से ऊपर, 246-7

[112] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 24. *क्यूबिलो* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 390 भी देखें, हालांकि यह कुछ मामलों में विवादास्पद है: क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 18-19.

[113] *क्यूबिलो* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 357।

[114] वही 245–6.

[115] *हालाँकि विलियम्स* [1999] एनएसडब्ल्यूएससी 843 ; (1999) 25 फैम एलआर 86 के मामले मेंइसे वादी द्वारा स्वीकार किया गया था।

[116] एटकिंसन, उपरोक्त एन 4, 81. क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 24 भी देखें. यह कानून मैकरे, उपरोक्त एन 99, [1.310] में सूचीबद्ध है.

[117] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 23.

[118] *ब्यूटेरा बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (विक्टोरिया)* [1987] एचसीए 58 ; (1987) 164 सीएलआर 180 ; *गेटली बनाम द क्वीन* [2007] एचसीए 55 ; (2007) 232 सीएलआर 208। जॉन लैंगबाइन, *द ऑरिजिन्स ऑफ एडवर्सरी क्रिमिनल ट्रायल* (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003)भी देखें

[119] डायना ईड्स, न्याय विभाग (क्वींसलैंड), *कोर्टरूम में आदिवासी अंग्रेजी: एक पुस्तिका* , (2000)।

[120] *उदाहरण के लिए, डायना ईड्स, कोर्टरूम टॉक और नियोकोलोनियल कंट्रोल* (माउटन डी ग्रुइटर, 2008)में चर्चा की गई गलतफहमी और उनके प्रभावों को देखें

[121] लापरवाही के न्यायसंगत सिद्धांत का प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के दावों के लिए अनुरूप अनुप्रयोग है।

[122] सामान्य नीतिगत विचारों की चर्चा के लिए, उदाहरण के लिए क्वींसलैंड कानून सुधार आयोग, *कार्रवाई की सीमा अधिनियम 1974 (क्वींसलैंड) की समीक्षा* , रिपोर्ट संख्या 53 (1998) अध्याय 2 देखें। 155 भी देखें, जहां आयोग ने चुराई गई पीढ़ियों के लिए अद्वितीय सीमाओं के लिए किसी भी उचित अपवाद पर विचार किया, और निष्कर्ष निकाला कि ऐसे मुकदमेबाजों को अन्य लोगों के समान स्थिति में होना चाहिए।

[123] जॉय विलियम्स को *विलियम्स बनाम द मिनिस्टर, एबोरिजिनल लैंड राइट्स एक्ट [नंबर 1]* (1994) 35 एनएसडब्लूएलआर 497 में न्यू साउथ वेल्स कोर्ट ऑफ अपील द्वारा अनुमति दी गई थी; क्रिस्टोफर जॉनसन को *जॉनसन* [1999] एनएसडब्लूएससी 1156 ; [2000] में न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति। अन्य सफल नहीं हुए हैं: लोर्ना क्यूबीलो और पीटर गनर ने *क्यूबीलो* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 443–8 में, विशेष रूप से इस पूर्वाग्रह के कारण कि गवाहों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रमंडल को नुकसान होगा।

[124] पहली रिट जॉय विलियम्स की थी, जिन्होंने 1993 में समय से बाहर अपनी रिट दाखिल करने के लिए नोटिस ऑफ मोशन द्वारा अनुमति मांगी थी। उनके आवेदन को पहले तो अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन न्यू साउथ वेल्स कोर्ट ऑफ अपील में अपील करने पर अनुमति दी गई: *विलियम्स बनाम मिनिस्टर एबोरिजिनल लैंड राइट्स एक्ट 1983* (अप्रकाशित, सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनएसडब्लू, स्टडर्ट जे, 25 अगस्त 1993); *विलियम्स बनाम मिनिस्टर, एबोरिजिनल लैंड राइट्स एक्ट, 1983 [संख्या 1]* (1994) 35 एनएसडब्लूएलआर 497 (एनएसडब्लू कोर्ट ऑफ अपील)। बाद में उनका मूल दावा विफल हो गया।ऊपर भाग । देखें।

[125] *माबो* [1992] एचसीए 23 ; (1992) 175 सीएलआर 1.

[126] जैकी कैटोना और चिप्स मैकिनोल्टी (संपादक), *द लॉन्ग रोड होम: द गोइंग होम कॉन्फ्रेंस* (कारू एबोरिजिनल चाइल्ड केयर एजेंसी, 1996)।

[127] ब्रूम, उपरोक्त एन 28, 51–3.

[128] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 3.

[129] जेनेट स्टेनली, एडम टॉमिसन और जूलियन पोकॉक, 'स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई समुदायों में बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा' (*राष्ट्रीय बाल संरक्षण क्लियरिंगहाउस मुद्दे,* संख्या 19, ऑस्ट्रेलियाई पारिवारिक अध्ययन संस्थान, वसंत 2003)।

[130] *उदाहरण के लिए, अल्बर्ट मेम्मी, द कॉलोनाइज़र एंड द कॉलोनाइज़्ड* (हॉवर्ड ग्रीनफ़ील्ड ट्रांस, बीकन प्रेस, 1967) 120–1 में चर्चा देखें, जहाँ वह उपनिवेशित लोगों की शर्म और आत्म-घृणा का उल्लेख करते हैं।

[131] लारिसा बेहरेंड्ट और लोरेटा केली, *स्वदेशी विवादों का समाधान: भूमि संघर्ष और उससे आगे* (फेडरेशन प्रेस, 2008) 97–100।

[132] *कार्टर बनाम कंपनी ऑफ द सिस्टर्स ऑफ मर्सी ऑफ डायोसीज रॉकहैम्पटन एंड ऑर्स* [2001] क्यूसीए 335 (28 अगस्त 2001); *आर बनाम ईआरजे* [2010] वीएससीए 61 (29 मार्च 2010) [51]। एनेट मार्फोर्डिंग, 'एक्सेस टू जस्टिस फॉर सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज' (1997) 5(2) *टॉर्ट्स लॉ जर्नल* 221 ; क्वींसलैंड लॉ रिफॉर्म कमीशन, उपरोक्त एन 121, अध्याय 14 'सरवाइवर्स ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज'; बेन मैथ्यूज, 'लिमिटेशन पीरियड्स एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज केस: लॉ, साइकोलॉजी, टाइम एंड जस्टिस' (2003) 11 *टॉर्ट्स लॉ जर्नल* 218 , 1.1 भी देखें।

[133] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 30.

[134] हेबिच, उपरोक्त एन 2, 601. वास्तव में, चोरी की पीढ़ी का सदस्य होने से कुछ परिस्थितियों में अपराधी की नैतिक दोषीता कम हो जाती है: रिचर्ड एडनी, 'चोरी की पीढ़ी और स्वदेशी अपराधियों की सजा' [2003] इंडिग्लॉब 16 ; (2003) 5(23) *स्वदेशी कानून बुलेटिन* 10.

[135] बेहरेंड्ट और केली, उपरोक्त एन 130, 73-85। राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान सलाहकार परिषद (एनएडीआरएसी), *स्वदेशी विवाद समाधान और संघर्ष प्रबंधन* (एनएडीआरएसी, 2006), 16 भी देखें।

[136] स्टेनली, टॉमिसन और पोकॉक, उपरोक्त एन 128, 12–13।

[137] न्याय तक पहुँच टास्कफोर्स, अटॉर्नी-जनरल विभाग (सीटीएच), *संघीय नागरिक न्याय प्रणाली में न्याय तक पहुँच के लिए एक रणनीतिक ढाँचा* (कॉमनवेल्थ सरकार, कैनबरा, 2009), 20.

[138] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 37.

[139] *क्यूबिलो* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 483।

[140] लिंडा पोपिक, 'कनाडा की चोरी हुई पीढ़ियों की भरपाई' [2008] इंडिग्लॉबी 4 ; (2008) 7(2) *स्वदेशी कानून बुलेटिन* 14.

[141] एटकिंसन, उपरोक्त एन 4, 87.

[142] जे.ए. डे मैयो, एट अल., *पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी बाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण: आदिवासी बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक भलाई को मापना और जबरन अलगाव के अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव* , (कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और टेलीथॉन इंस्टीट्यूट फ़ॉर चाइल्ड हेल्थ रिसर्च, 2005); चिस क्यूनेन और टेरी लिब्समैन, 'रिमूव्ड एंड डिस्कार्डेड: द कंटेम्पररी लिगेसी ऑफ़ द स्टोलन जेनरेशन' [2002] AUIndigLawRpr 55 ; (2002) 7(4) *ऑस्ट्रेलियाई स्वदेशी कानून रिपोर्टर* 1.

[143] *विलियम्स* (1999) 125 फ़ैम एलआर 86 , [846]–[865]। अपील की अदालत भी इस कठिनाई पर ज़ोर देती है: *विलियम्स बनाम मंत्री, आदिवासी भूमि अधिकार अधिनियम 1983* (2000) ऑस्ट टॉर्ट्स रिपोर्ट 81-578, [157]–[158]।

[144] *क्यूबिलो* [2000] एफसीए 1084 ; (2000) 103 एफसीआर 1 , 388। वैलेरी लिनोव के न्यू साउथ वेल्स अपराध मुआवजा न्यायाधिकरण के पीड़ितों के शुरुआती आवेदन में एक समान परिणाम हुआ, जो उसके परिवार से हटाए जाने और देखभाल में रखे जाने के बाद एक यौन हमले में हुए नुकसान के लिए था: क्रिस्टीन फोर्स्टर, 'चोरी पीढ़ी और पीड़ित मुआवजा न्यायाधिकरण: यौन हमले के लिए प्रतिपूरक निवारण के अधिकार को "लिखने" के लिए आदिवासी होने का "लेखन इन" [2002] यूएनएसडब्ल्यूलॉजेएल 7 ;) 25(1) *न्यू साउथ वेल्स लॉ जर्नल* 185 , 191-2; एलेक्सिस गुडस्टोन, 'पीड़ित मुआवजा न्यायाधिकरण में चोरी पीढ़ियों की जीत' [2003 (2003) 5(22) *स्वदेशी कानून बुलेटिन* 10.

[145] *ट्रेवोरॉव बनाम स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया (सं. 5)* [2007] एसएएससी 285 ; (2007) 98 एसएएसआर 136 , 387, 393.

[146] वही 393.

[147] *ट्रेवोरॉ* [2008] एसएएससी 4 (1 फरवरी 2008)। उपरोक्त एन 13 भी देखें।

[148] *क्यूबिलो* [2000] एफसीए 1084 ; [2000] 103 एफसीआर 1 , 474-9।

[149] *विलियम्स* (1999) 125 फैम एलआर 86 , [867]–[1038]।

[150] क्यूनीन और ग्रिक्स, उपरोक्त एन 24, 21.

[151] *उन्हें घर लाना* , उपरोक्त एन 3, 264.

[152] *नुल्यारिम्मा बनाम थॉम्पसन* [1999] एफसीए 1192 ; (1999) 96 एफसीआर 153 ; *बज़ाकॉट बनाम हिल* [1999] एफसीए 639 (10 मई 1999); गुइलफॉयल, उपरोक्त एन 101; रॉबर्ट वैन क्रिएकेन, 'क्या आत्मसात न्यायसंगत है? *लोर्ना क्यूबिलो और पीटर गननर बनाम द कॉमनवेल्थ*' [2001] सिडलॉरव 10 ; (2001) 23 *सिडनी लॉ रिव्यू* 239 ; मार्कोविच, उपरोक्त एन 101; शिर्लेने रॉबिन्सन और जेसिका पैटेन, 'नरसंहार और स्वदेशी बाल निष्कासन का प्रश्न: औपनिवेशिक ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ' (2008) 10(4) *जर्नल ऑफ़ जेनोसाइड रिसर्च* 501 ; रॉबर्ट वैन क्रिएकेन, 'सांस्कृतिक नरसंहार पर पुनर्विचार' (2008) 12 *ऑस्ट्रेलियाई स्वदेशी कानून रिपोर्टर* 76 ; जूली कैसिडी, 'अनुपयोगी और अनुचित?: नरसंहार और चोरी की पीढ़ियों का सवाल' (2009) 13(1) *ऑस्ट्रेलियाई स्वदेशी कानून रिपोर्टर* 114.

[153] बेहरेंड्ट, क्यूनीन और लिब्समैन, एन 100 से ऊपर, 246-7।

[154] आदिवासी बुजुर्ग हेरोल्ड थॉमस द्वारा डिजाइन किया गया और पहली बार 1971 में फहराया गया आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई ध्वज को *ध्वज अधिनियम 1953* (सीथ) के तहत ऑस्ट्रेलियाई ध्वज नामित किया गया था, जब जुलाई 1995 में गवर्नर-जनरल द्वारा इसे इस रूप में घोषित किया गया था: ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल, *राजपत्र* , संख्या एस 259 (1995)।

[155] इस कानून ने कुछ परिस्थितियों में नस्ल, रंग, वंश या राष्ट्रीय या जातीय मूल (धारा 9) के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना अवैध बना दिया और राष्ट्रमंडल और राज्यों को बाध्य किया (धारा 6)।

[156] रिचर्ड चिशोलम, 'प्लेसमेंट ऑफ़ इंडिजिनस चिल्ड्रन: चेंजिंग द लॉ' [1998] यूएनएसडब्ल्यूलॉज19 ; (1998) 21(1) *यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स लॉ जर्नल* 208.

[157] *साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम लैम्पार्ड-ट्रेवोर* [2010] एसएएससी 56 (22 मार्च 2010), [389]।

[158] बेहरेंड्ट, क्यूनीन और लिब्समैन, एन 100 से ऊपर, 44-46।